

उत्तर शीत युद्ध काल में भारत – रूस रक्षा सहयोग

डॉ० राजेश कुमार

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग एस० एस० एस० वी० एस० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार, मीरजापुर

भारत और रूस के सदियों से मधुर सम्बन्ध समय की कसौटी पर खरे उतरे। रक्षा सहयोग और पारस्परिक हितों से सम्बन्धित सामरिक समझौते की एक लम्बी श्रृंखला रही है। इस सहयोगात्मक विरासत को साथ लेकर भारत और रूस ने 21वीं शताब्दी में प्रवेश किया, जिन्हें अनेक अद्यतन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शीतयुद्धोत्तर काल के बदलते सन्दर्भों एवं वैश्वीकरण की नीतियों के बढ़ते प्रसार ने दोनों देशों के सम्बन्धों में एक नया आयाम जोड़ा है। सदियों से दोनों देश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक साझा वैचारिक संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में सोवियत संघ एक प्रेरणा स्रोत रहा है तथा सामाजिक, सैनिक और आर्थिक हितों की समानता से संचालित विदेश नीति ने दोनों देशों को एक-दूसरे के करीब खड़ा किया।

भारत के स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् दोनों देशों के सम्बन्धों ने ठोस रूप धारण किया। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक उपक्रम, जिसमें रक्षा क्षेत्र भी शामिल था, की स्थापना में एक अहम भूमिका अदा की। ऐतिहासिक सन्दर्भों के विश्लेषण से हम पाते हैं कि पाक को अमरीकी सहायता, रूस और चीन के बीच मतभेद, भारत और अमरीका के बीच बढ़ती दूरी, चीन-अमरीका का अर्धसैनिक गठबन्धन, चीन और पाक की रणनीतिक धुरी और अमरीका तथा पाक के सैन्य गठबन्धन ने सोवियत रूस के विदेश नीति-निर्माताओं को तृतीय विश्व की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु भारत के साथ मधुर और सक्रिय सम्बन्ध बनाने हेतु अभिप्रेरित किया। अन्य देशों के विपरीत सोवियत संघ ने भारत को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया, तकनीकी हस्तान्तरण की बात की तथा भारत को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराया, जिसने न केवल भारत के सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना का काम किया, बल्कि 1955 के बाद भारत में रक्षा उपक्रमों की स्थापना का आधार बना।

1959 से भारत ने सोवियत संघ के रक्षा उपकरणों को खरीदना स्वीकार किया। भारत द्वारा सोवियत रक्षा उपकरणों को खरीदना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इन सौदों का भुगतान रुपये में किया जाना था। साथ ही साथ रूस ने इन सौदों पर भारत को भारी छूट दी। यह भारत-रूस सम्बन्धों के क्रम में भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय भारत आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था, साथ ही साथ उसे रक्षा उपकरणों की भी अतिशय आवश्यकता थी, ताकि भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों से सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सके। नवम्बर 1959 के प्रारम्भ में दोनों देशों ने एक सहमति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये, जिसके द्वारा रूस ने भारत को आठ ए0एन0-12 वायुयान तथा एम0आई0-4 हेलीकाप्टर देने की बात कही, जो भारत-तिब्बत सीमा पर तैनात किये जाने थे। इस समझौते के बाद कुछ लोगों द्वारा

यह आशंका भी व्यक्त की जाने लगी कि कहीं भारत सोवियत संघ का उपग्रह न बन जाये। चीन ने इस सन्धि और सहयोग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सोवियत संघ द्वारा भारत को व्यापक सैन्य सहायता का आरोप लगाया तथा इस गठबन्धन को अपने विरुद्ध माना।

1965 के भारत-पाक युद्ध में मास्को औपचारिक रूप से निष्पक्ष रहा, लेकिन उसने भारत को हथियारों की आपूर्ति जारी रखी। 1965-1969 का काल सोवियत संघ में रक्षा उत्पादन का सर्वोच्च दौर था। यह इसलिए सम्भव हो सका कि भारत अपने कुल रक्षा सौदों के 80 प्रतिशत आयात हेतु सोवियत पर निर्भर था। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पूर्वी पाक में मानवीय संकट के दौर में भारत और सोवियत संघ ने 9 अगस्त, 1971 को 'शान्ति, मित्रता एवं सहयोग' की एक ऐतिहासिक सन्धि की। इस सन्धि ने भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिका तथा चीन को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से दूर रखा।

यद्यपि भारत की सोवियत संघ पर रक्षा निर्भरता बढ़ती रही तथा दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार में वृद्धि भी होती रही, लेकिन 1977 में सत्ता पर काबिज हुई जनता पार्टी की सरकार रूस पर अपनी पूर्ण रक्षा निर्भरता को समाप्त करना चाहती थी तथा रक्षा व्यापार को विविधकृत आयात देना चाहती थी। इस सन्दर्भ में भारत ने ब्रिटेन के साथ 116 जगुआर बमवर्षक और समुद्र के अन्दर चलने वाले फाइटर्स पोत खरीदने का प्रस्ताव रखा। चार पनडुब्बी पश्चिम जर्मनी से खरीदने का और 40 मिराज 2000एच0 फ्रान्स से खरीदने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मास्को ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अद्यतन तकनीकी आपूर्ति रोकने की बात कही। 1980 में श्रीमती गाँधी के पुनः प्रधानमंत्री बनने पर भारत ने सोवियत संघ का राजनीतिक समर्थन करना कुछ कम कर दिया, क्योंकि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया था। यद्यपि भारत ने इस मुद्दे पर बहुत ही सावधानीपूर्वक कार्य किया।

शीत युद्ध के अन्त ने विश्व के भू-राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया तथा पूर्व सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस और दूसरे परवर्ती राज्यों को अपने हितों के लिए जटिल गठजोड़ और लाभ पर आधारित नये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को बनाना जरूरी हो गया। भारत, जो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का प्रणेता और सोवियत संघ का घनिष्ठ व्यापारिक एवं रक्षा सहयोगी हुआ करता था, नई परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपने सम्बन्धों को रूस के साथ मजबूत बनाया तथा बदलती परिस्थितियों में रक्षा सहयोग को क्रेता-विक्रेता के सम्बन्धों से ऊपर उठकर तकनीकी के संयुक्त विकास के स्तर तक सम्बन्ध स्थापित किया। रक्षा सहयोग भारत-रूस सामरिक साझेदारी का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय सेना को 60 प्रतिशत

सैनिक उपकरणों के कल-पुर्जे सोवियत संघ से ही प्राप्त होते थे। शीतयुद्ध की समाप्ति और 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक सम्बन्धों की प्रकृति में उल्लेखनीय बदलाव आये हैं। फिर भी रूसी संघ और भारत अपने घनिष्ठ और दोस्ताना सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने के लिए एक नया आधार तलाशने में सफल रहे।¹

मास्को और नई दिल्ली के बीच सैन्य सम्बन्ध उनके आपसी सम्बन्धों के प्रतीक थे। रूस एवं नई दिल्ली के बीच सम्बन्ध बड़े गहरे, वृहद एवं टिकाऊ थे। भारत एक ऐसे रूस से सम्बन्ध बनाये था, जो यूरोपीय देशों पर आश्रित था और आर्थिक रूप से पश्चिमी सहायता पर निर्भर था, जहाँ न तो उसका हित सधता था और न पश्चिमी शासकों से आश्रय मिल पाता था। भारत और सोवियत संघ में जो सम्बन्ध और पारस्परिक लाभ था, वह विशिष्टताएँ रूस के साथ फीकी पड़ गईं और आपसी हित की सम्भावनाएँ कहीं गायब हो गईं। नयी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो आपसी हितों को प्राप्त करने के अवसर थे, वे पारस्परिक हित वाले केन्द्र बिन्दु गायब होने लगे और नवस्थापित हितों के बीच टकराव की सम्भावनाएँ बढ़ गयीं। लेकिन इसके साथ ही कुछ पूर्व मतभेद खत्म हो गये और नये समय में कुछ हित, जो दोनों के लिए सामान्य थे, वे इन हालातों के बाद भी बने रहे और नयी क्षतिपूरक परिस्थितियाँ उभर आयीं। दोनों देशों के बीच कुछ पारस्परिक हित प्रासंगिक बने रहे। भारत मास्को की एशियाई नीति का केन्द्र बिन्दु बना रहा तथा आपसी स्पष्ट समझदारी के कारण उसके आपसी सम्बन्ध कायम रहे। रूस-भारत रक्षा सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए रक्षात्मक तरीके अपनाये गये, जिसे येल्लसिन के आगमन पर आगे मजबूती प्रदान की गयी। स्थायित्व प्रदान करने का दूसरा कारण रूस की एशियाई पहचान थी। इस प्रकार रूस और भारत ने संकट के समय एक-दूसरे की सहायता की।

क्रायेोजेनिक इंजन की बिक्री के मामले में रूस और भारत पर अमेरिकी दबाव ने दोनों देशों के एक-दूसरे के और करीब ला दिया। नये हालात में अमेरिका के लिए यह पहली रूसी चुनौती थी। येल्लसिन के आगमन से सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता यह मिली कि नई मैत्रीपूर्ण सन्धियों पर हस्ताक्षर के साथ कई अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बन्धों को

मजबूत करने के लिए कुछ दूसरे समझौते हुए। 1971 की "शान्ति, मित्रता एवं सहयोग" वाले मामले को छोड़कर 1993 वाले "मैत्रीपूर्ण सन्धि एवं सहयोग" वाले समझौते में रूस या भारत पर संकट के समय सैनिक विमर्श के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जो किसी भी पक्ष को एक-दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य सैन्य गठजोड़ से रोक सके या किसी तीसरे पक्ष द्वारा युद्ध छेड़ने पर आपस में किसी पक्ष को उसकी सहायता करने से रोके। इस प्रकार नयी सन्धि के शीर्षक से 'शान्ति' शब्द हटाने का महत्त्व जाना जा सकता है।

रक्षा सहयोग भारत-रूस सम्बन्धों का एक प्रमुख अंग है, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद यह कमजोर पड़ गया। 1992 में रूस ने लगभग चार अरब डालर मूल्य के रक्षा उपकरणों का भारत को निर्यात किया। 90 के दशक की शुरुआत में भारत के लिए अल्पकालीन चिन्ता इस बात के लिए थी कि हथियारों के कल-पुर्जे सीमित मात्रा में मिलते थे और सोवियत हथियारों की आपूर्ति कम थी। सोवियत उत्पादित सामग्री पर निर्भरता के तीन दशक बाद 1991 में भारत इस स्थिति में आ गया कि उसके पास सेना के 70 प्रतिशत हथियार रूसी मूल के थे।² रक्षा उपकरणों के कल-पुर्जे के निर्माण और आपूर्ति में देशी क्षमता की कमी के कारण भारतीय सेना को तत्कालिक संकट का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ के विघटन से सोवियत सैन्य आपूर्ति को झटका लगा क्योंकि सोवियत उद्योगों का प्रशासनिक और उनकी वास्तविक स्थिति नवनिर्मित स्वतंत्र राज्यों में फैली हुई थी।

पिछले कुछ सालों में रूस से जो बृहद आयुध प्रणाली प्राप्त की गयी या समझौता हुआ था, उनमें प्रमुख हैं— सुखोई-30 एम0के0आई0 बहुपयोगी लड़ाकू विमान, टी0-78 टैंकर, किलो क्लास/टाइप 877 पनडुब्बियाँ, के0ए0-31 हेलिकॉप्टर वायुजनित पूर्ण चेतावनी वाले हेलीकॉप्टर, विमानवाहक एडमिरल गोरशकोव, मिग-29 के, के0ए0-27 तथा टी-90 टैंक, अग्नि नियंत्रक राडार, वायु तथा सागर में निगरानी करने वाले राडार, युद्धक राडार, टैंक तथा पोत रोधी प्रक्षेपास्त्र आदि।

India's Imports from Russia, 2005-2010

Weapon designation	Weapon description	No. Delivered/ Produced	Year(s) of Deliveries	Comments
Kopyo	Aircraft radar	125	2001-2006	-
Kh-31A1/ AS-17	Anti-ship missile	200	2000-2007	-
3M-54 Klub/SS-N-27	Anti-shipmissile	150	2001-2008	-
II-38SD/May	ASW aircraft	3	2008	Indian II-38 rebuilt to II-38SD
II-38/May	ASW aircraft	2	2009	Ex-Russian; modernized to II-38SD version before deloivery
MiG-29SMT/ Fulcrum	FGA aircraft	10	2010	For use on Gorshkov (Vikramaditya) aircraft carrier
Su-30MK/ Flanker	FGA aircraft	18	2007-2008	Su-30MKI version; exchanged for 18 Indian Su-30K (replacing original planned modernization of Su-30K to su-30MK)
Su-30MK/ Flanker	FGA aircraft	26	2009-2010	\$ 1.5-1.6 b deal; Su-30MKI version; assembled from kits in India; delivery 2009-2011/2012
AK-630 30mm	Naval gun	20	1998-2005	For 3 Brahmaputra (Project-16A) frigates and 4 Kora (Project-25A) corvettes produced in India.

T-90S	Tank	310	2001-2006	(L)
T-90S	Tank	150	2009-2010	(L) \$866 m deal (part of \$2.5 b deal); option on some 700 more; assembled in India ; delivery 2009-2011/2012
PJ-10 BrahMos	Anti-ship missile	110	2006-2010	(L) Version of Yakhont (SS-N-26); officially joint venture for development but mainly using Russian technology; in-ship-launched, air-launched and submarine-launched and land-based version.
Su-30MK/ Flanker	FGA aircraft	75	2004-2010	(L) \$3-5.4 b deal; Su-30MKI version; delivery 2004-2014/2015

Source: Stockholm International Peace Research Institute, Trade Register Table of Major Conventional Weapons Transfers from Russia to China, generated 19 November 2011 at <http://www.ripi.org>.

भारतीय रक्षा तंत्र रूसी रक्षा आपूर्ति पर निर्भर है। सोलह में से बारह समुद्री पनडुब्बियाँ रूसी मूल की हैं। द्वितीय श्रेणी के पाँच कासिन विध्वंसक तथा तृतीय श्रेणी के तीन क्रिवाक युद्धपोत भी रूसी देन के हैं। डेढ़ मिलियन डालर की कीमत वाला रूस का विशाल विमानवाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव (भारतीय नाम विक्रमादित्य) भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। भारत ने रूस से 347 और मुख्य युद्धक टैंक, 80 और एम0आई0-17 मार करने वाले हेलीकाप्टर रूस से खरीदे। भारतीय वायु सेना 50 बहुपयोगी सुखाई-30 एम0के0आई0 पूना एवं बरेली में बना रही है। एक हाल ही के समझौते में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने भारत में 40 और सुखाई लड़ाकू विमानों को आधुनिक करने की सहमति प्राप्त की, जिसमें रूसी निर्मित राडार और ब्रह्मोस सुपर सोनिक मिसाइल का इस्तेमाल होगा। यह 2.3 बिलियन डालर का प्रोजेक्ट 2012 में शुरू हुआ। इस दशक के अन्त तक भारत के पास 280 सुखाई लड़ाकू विमान होंगे।³

रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दिसम्बर 2004 में भारत आगमन, भारत-रूस रक्षा सम्बन्धों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण में, विशेषतया दक्षिण एशिया सुरक्षा के सन्दर्भ में यह अहम सिद्ध हुआ। यह भारत की वैश्विक आकांक्षाओं और भारत की सम्पूर्ण सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। सन् 2004 में रूसी राष्ट्रपति के आगमन पर जो बड़े मुद्दे उभर कर सामने आये, वे हैं—रूस और भारत क्रेता-विक्रेता सम्बन्धों से उठकर संयुक्त अनुसंधान एवं विकास तथा आयुध प्रणाली के संयुक्त उत्पादन के स्तर पर आ गये। दोनों देशों ने पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के संयुक्त उत्पादन की सम्भावनाएं तलाशी, रक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में बौद्धिक सम्पदा अधिकार समझौते को अंतिम रूप दिया, मौजूदा रूसी आयुध प्रणाली को उन्नत रूप देने के समझौते पर हस्ताक्षर किये और भारत की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कल-पुर्जा की आपूर्ति पर विचार-विमर्श हुआ और इसके तौर-तरीके सुनिश्चित किये गये। संयुक्त अनुसंधान एवं विकास तथा आयुध प्रणाली के उत्पादन पर विशेष ध्यान कई मायने में उल्लेखनीय रहा। भारत के लिए यह फायदा हुआ कि इसकी आयुध क्षमता में परिणात्मक वृद्धि हुई तथा पहले से ज्यादा आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई।⁴ रूसी राष्ट्रपति मेदवदेव ने 2008 की अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य हथियारों के बेचने और खरीदने की अपेक्षा सामूहिक रूप से उनका डिजाइन और उत्पादन करना है, जैसा कि अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश करते हैं।⁵

रूस से आपूर्ति के बावजूद भारत ने इजरायल और अमेरिका जैसे अन्य आपूर्तिकर्ताओं से दूरी नहीं बनायी है ताकि सोवियत संघ के विघटन के बाद के दिनों में सेना के सामने आई आपूर्ति सम्बन्धी दिक्कतों का दोबारा सामना न करना पड़े। हाल के सौदों में नये सिरे से उपकरणों से लैस किये गये सोवियतकालीन विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव की ब्रिक्री समझौता भी शामिल है। इसके अलावा गोर्शकोव विमान वाहक पोत से मिग-29 लड़ाकू जेट का संचालन कर सकने की सुविधा का विकास किया जाना है। पुतिन की विदेशी नीति सहयोगी यूरी ऊषाकोव ने कहा कि नया समझौता दोनों पक्षों के अनुरूप होगा।

भारत और रूस के मध्य सामरिक सौदे में सबसे बड़ा सौदा 1998 में हुआ, जब दोनों देशों ने संयुक्त उपक्रम के द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के उत्पादन का फैसला किया। वर्तमान में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का उत्पादन रक्षा क्षेत्र में भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस उपलब्धि ने भारत को उन गिने-चुने देशों के बीच ला खड़ा किया है, जिन्होंने क्रूज मिसाइल उत्पादन की क्षमता हासिल कर ली है। संयुक्त रूप से उत्पादित यह क्रूज मिसाइल दूसरों से अलग है, जो ध्वनि से भी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण खूबी यह है कि अत्याधुनिक एवं उच्चतम तकनीक के प्रयोग के कारण इसका कोई दूसरा प्रतिद्वन्दी नहीं है। अदृश्य रहने वाली तमाम खूबियों के साथ इस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 280 किलोमीटर है। इसे इसी पर लगे एक कम्प्यूटर की सहायता से गाइड किये जाने की क्षमता को परखा जा चुका है। कम्प्यूटर और गाइडेंस प्रणाली को भारत में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है जबकि रूस को मशीनोस्टाइनी ने इसका प्रोपल्शन सिस्टम तैयार किया है।⁶

इस एंटी शिप मिसाइल की सबसे महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इसे भूमि, समुद्री पोत, पनडुब्बी या हवा कहीं से भी लानच किया जा सकता है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि इसका उत्पादन देश की परमाणु नीतियों के अनुसार हुआ है। वैसे भी तल्खी और विवाद से बचने के लिए रूस और भारत ने इसके उत्पादन में उन बातों का खयाल रखा है जिससे परमाणु अप्रसार के मामले में एम0टी0सी0आर0 या अन्य सन्धियों का उल्लंघन न हो, यही कारण है कि मिसाइल की मारक क्षमता की रेन्ज 300 किमी0 से कम रखी गयी है।⁷ भारत और रूसी सेना में इसे शामिल करने से पहले भी श्रृंखलाबद्ध रूप से इसके तमाम परीक्षण हो चुके हैं। ब्रह्मोस

मिसाइल में समाहित अत्याधुनिक तकनीकी को मास्को, चीन या अन्य किसी देश को नहीं उपलब्ध कराया।

भारत ने अमेरिका की चेतावनी को नजर अन्दाज करते हुए अक्टूबर 2018 में रूस के साथ बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम समझौते को अन्तिम रूप दे दिया। एस-400 रूस का सबसे अत्याधुनिक जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। रूस से खरीदी जा रही एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा रखने वाले पड़ोसी देशों से भारत को जरूरी सुरक्षा उपलब्ध करायेगी। वायु सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी एयर मार्शल आर० नाबियार के अनुसार भारत को यह प्रणाली अगले 23 महीनों में मिल जायेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कहा "भारत रूस के साथ अपने सम्बन्धों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तेजी से बदलते युग में हमारे सम्बन्ध और भी प्रासंगिक हो गये हैं"।⁹

रूसी तकनीकी अब भी अधिकतर भारतीय सैन्य हथियारों का मुख्य आधार बनी हुई है जो भारतीय सैन्य उपकरणों का लगभग 70 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त रूस के कुल वार्षिक रक्षा निर्यातों का 40 प्रतिशत भारत आयात करता है तथा आने वाले कुछ वर्षों में विभिन्न समझौतों को देखते हुए यह अनुपात 50 प्रतिशत तक जा सकता है।⁹ बाजार सहभागिता बनाये रखने के प्रयास के रूप में रूस ने भारत को अपने अत्यन्त उन्नत सैन्य तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव किया है, जिसके बदले में भारत को रूस का सबसे बड़ा हथियार आयातक बने रहना होगा। रूस द्विपक्षीय सम्बन्धों में भारतीय माँग के अनुसार क्रेता-विक्रेता के सम्बन्धों से आगे चलकर हथियारों के संयुक्त उत्पादन और विपणन में सहयोग कर रहा है।

संदर्भ- ग्रन्थ

1. Kumar, Ranjan, "Indo-Russia Defence cooperation in Chopra, V.D. (ed.) Significance of Indo-Russian Relations in 21st Century, Kalpaz publications, Delhi, 2008, p. 144
2. Radyuhin, Vladimir, "India-Russia Diversify Defence Tie-up" "The Hindu (International Edition), 18 October, 1997, p. 12
3. मिश्रा, रंजना, "भारत और रूस : राजनीतिक तालमेल का महत्व", वर्ल्ड फोकस, अंक-01, दिल्ली, जनवरी 2011, पृष्ठ 9
4. Kapila, Subhash, "Russia : President Putin's Visit to India" South Asia Analysis Group, New Delhi, January 2007
5. Reuters, "Russia and India Sign Nuclear pact" International Herald Tribune, 5 December 2008
6. India and Russia to Develop Hypersonic cruise Missile, RIA Novosti, 30 March 2012, <http://en.rai.ru/world/20120330/172478672.html>
7. Ibid
8. www.navbharattimes.com, 05 oct. 2018
9. According to the Russia center for Analysis fo International weapons Trade, India will account for 54% of Russian arms export from 2010 through 2013, estimated at over USD 15 billion
10. Das Kundu, Nivedita, "Vladimir Putin's Presidency and India-Russia Relationship," Valdai International Discussion club. 24 May 2012